THE MINISTER OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI S. B. CHAVAN): (a) to' (c) The Ministry of Social Welfare have recently received letter from Age-Care India describing its activities. However, neither the Del'hi Administration nor the Ministry has received any application for assistance from the organisation.

Controlling the indiscriminate Growth of Colleges in the country

2594. SHRI ROBIN KAKATI: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether the Central Government have any plan to check the indiscriminate growth of colleges throughout the country; -and

(b) if so, what ,are the salient features of the same?

THE MINISTER OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI S. B. CHAVAN); (a) and (b) The pri. mar$_v$ responsibility for establishment of new colleges- in any State is that of the State Governments. While the Central Government, do not have any plan as such to check the growth in the number of colleges in the States, the main thrust in the Sixth Five Year Pla$_n$ 1980-85, as approved by the National Development Council, is to coordinate the existing facilities and maximising -their utilisation. The Sixth Five Year Plan also suggests that the problem of non-viable insti-tutions, with low enrolments and inadequate-provisions of facilities, as well as proliferation of such institutions, offering general academic courses, would need to be tackled with determination, by the State Gov. ernment$_s$ and the University Grants Commission in order to avoid increasing unemployment among the graduates as well as to make better use of the available resources for educational development.

ग्रामीण इलाकों में चीनी का अभाव

2595. **श्री कलराज मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में चीनी का अत्यधिक अभाव है तथा ग्रामीण इलाकों में इस तथ्य के बावजूद पिछले छः महीनों से चीनी वितरित नहीं की गई है कि गन्ने की पेराई का मौसम पहले ही शुरू हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो चीनी के अभाव के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) जी नहीं। सम्बन्धित राज्य सरकारों में प्रचलित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दोनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कुल 2.71 लाख मीटरी टन लेवी चीनी के मासिक कोटों की निर्मुक्ति की जा रही है। इसके अलावा, खुले बाजार में बिक्री करने के लिए भी प्रत्येक मास पर्याप्त मात्रा में चीनी निर्मुक्ति की जा रही है। सरकार के पास किसी भी राज्य में गत छः महीनों में ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी का वितरण न करने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

Despatch of rice to Nagaland

2596. SHRI HARVENDAR SINGH HANSPAL: Will the-Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it i$_s$ a fact that rice worth Rs. 30 crores despatched by the Centre for Nagaland was sold in Nepal and Bangladesh in the recent past;

(b) if so, whether any inquiry has been instituted by Government in this regard; and

(c) if so, what are the findings thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (MISS KAMALA KUMARI): (a) No, Sir. No such information is available cither with the Government or Food Corporation of India to the effect that rice worth 30 crores despatched by the Centre for Nagaland was sold in Nepal and Bangladesh. Rice for Nagaland is despatched to Dimapore Railhead with consigner and consignee being Food Corporation of India. These stocks are released only to the nominees of the State Government as per allocations made by them. The subsequent movement/issue^ are being controlled by the State Government. Allo'ment of rice to Nagaland from the Central Pool is made on monthly basis which is of the order of 4 thousand tonnes. Even the total quantity allotted to Nagaland for a'whole year would cost- only Rs. 8.10 -crores.

(b) and (c)'Do not arise.

उत्तर प्रदेश में नई चीनी मिलों की स्थापना

2597. श्री कलराज मिश्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उत्तर प्रदेश में जिले-वार कितनी चीनी मिलें खोली जाने का प्रस्ताव है और क्या प्रत्येक जिले में इन मिलों के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इन मिलों पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सहकारी क्षेत्र में निम्नलिखित बारह चीनी मिलें स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र दिए हैं :—

क्रम सं०	प्रस्तावित स्थान जिला समेत	क्षमता टी०सी० डी०
1.	सितारगंज, जिला नैनीताल	1250
2.	मोरना, जिला मुजफ्फरनगर	—वही—
3.	घोसी, जिला आजमगढ़	—वही—
4.	हंसा, जिला बरेली	—वही—
5.	नानपारा, जिला बहराइच	—वही—
6.	सम्पूर्णनगर, जिला खीरी	—वही—
7.	अकबरपुर, जिला फैजाबाद	—वही—
8.	मठ, जिला मथुरा	—वही—
9.	पूर्णपुर, जिला पीलीभीत	—वही—
10.	सैयदपुर, जिला बुलन्दशहर	—वही—
11.	बहजोई, जिला मुरादाबाद	—वही—
12.	पोवायन, जिला शाहजहांपुर	—वही—

राज्य सरकार ने सितारगंज, जिला नैनीताल में प्रस्तावित चीनी मिल के लिए स्थान के बारे में फैसला कर लिया है । राज्य स्थान चुनाव समितियां तीन और प्रस्तावित चीनी मिलों अर्थात् (1) घोसी, जिला आजमगढ़ (2) मोरना, जिला मुजफ्फरनगर, और (3) हंसा, जिला बरेली के लिए भी स्थानों के बारे में विचार कर रही हैं ।

(ग) अनुमान है कि प्रत्येक प्रस्तावित नयी चीनी मिल पर लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत आएगी ।